

## मुख्य समाचार

- पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के निधन पर सात दिनों का राजकीय शोक घोषित, राष्ट्रपति द्वौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की।
- राज्य में सात दिनों के राजकीय शोक की अवधि में नहीं होंगे सरकारी समारोह, सरकार ने 28 दिसंबर को रांची में आयोजित मईयां सम्मान योजना कार्यक्रम को किया स्थगित।
- पश्चिम सिंहभूम जिला प्रशासन ने विभिन्न उग्रवादी हिंसा में मारे गये तेरह व्यक्तियों और सरकारी सेवाओं में कार्यरत 34 कर्मियों के आश्रितों को स्थायी नौकरी देने का लिया निर्णय।
- दामोदर नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए धनबाद में लगाया जायेगा सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, त्रिपक्षीय समझौते पर किया गया हस्ताक्षर।
- रांची में जनवरी में होने वाली 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेलों प्रतियोगिता की तैयारी अंतिम चरण में, तीन जनवरी से खिलाड़ियों का होगा आगमन।

\*\*\*\*\*

केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर सात दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और कोई भी सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। दिवंगत का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जायेगा। विदेशों में स्थित सभी भारतीय मिशनों और दूतावासों में भी अंतिम संस्कार के दिन राष्ट्र ध्वज आधे झुके रहेंगे।

\*\*\*\*\*

इधर राज्य सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर सात दिनों का राजकीय शोक मनाने की घोषणा की है। इस अवधि में राज्य के सभी सरकारी भवनों, जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराये जाते हैं, वहां ये ध्वज आधे झुके रहेंगे। इसके साथ ही किसी प्रकार का राजकीय समारोह आयोजित नहीं किया जायेगा। राज्य सरकार ने 28 दिसंबर को नामकोम में होने वाले मईयां सम्मान योजना का कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया है।

\*\*\*\*\*

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा गया है जहां देशभर के नेता पहुंचकर भावभीनीं श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्वौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, ने उनके आवास पर पहुंचकर दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि डॉ मनमोहन सिंह का संघर्षपूर्ण जीवन भावी पीढ़ी के लिए अनुकरणीय है।

\*\*\*\*\*

चौथा सुशासन सप्ताह 2024 और 'प्रशासन गाँव की ओर' अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने इस अभियान का आयोजन इस महीने की 19 से 25 तारीख तक किया। यह नागरिक-केंद्रित शासन और सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी पर केंद्रित भारत का सबसे बड़ा अभियान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 'प्रशासन गाँव की ओर' केवल एक नारा नहीं है, बल्कि प्रभावी शासन को ग्रामीण समुदायों के करीब लाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी प्रयास है।

\*\*\*\*\*

पश्चिम सिंहभूम जिला प्रशासन ने विभिन्न उग्रवादी घटनाओं में 13 मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सरकारी सेवाओं में स्थाई नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। जिला स्तरीय अनुकंपा समिति ने इसका अनुमोदन किया है। समिति ने ज़िले में उग्रवादी घटनाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों से आवेदन मांगा था। समिति ने सरकारी सेवाओं में कार्यरत मृत व्यक्तियों के 34 आश्रितों को भी नियुक्ति देने का निर्णय लिया है।

\*\*\*\*\*

दामोदर नदी को प्रदूषण मुक्त करने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए धनबाद में सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जायेगा। इसके लिए नई दिल्ली स्थित नमामि गंगे कार्यालय में त्रीपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। समझौते पर स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन, जुड़को और धनबाद वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया। इस परियोजना पर पांच सौ 18 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इसके तहत पांच सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाये जायेंगे।

\*\*\*\*\*

आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी  
वेबसाईट news on air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।  
ताजा समाचार एक्स हैंडल **@AIR news alerts** और फेसबुक पेज

All India Radio news पर भी उपलब्ध है।

आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल

**@AIR news अंडर र्स्कोर\_ranchi**  
और

फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा

**YOUTUBE Channel AIR NEWS Ranchi**

पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।

\*\*\*\*\*

धनबाद जिले के उप विकास आयुक्त सादात अनवर ने कहा कि वैध उत्थनन कार्य निर्बाध रूप से चले, यह सुनिश्चित करना खनन टास्क फोर्स का काम है। कोयले के अवैध खनन पर लगाम लगाना भी खनन टास्क फोर्स का दायित्व है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन ने कहा कि कोयले का खनन बाधित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

\*\*\*\*\*

आकाशवाणी समाचार अपनी विशेष वर्षांत शृंखला में विभिन्न मंत्रालयों की वर्ष 2024 की झलकियाँ प्रस्तुत कर रहा है। आज, पर्यटन मंत्रालय की प्रमुख पहलों और उपलब्धियों पर डालते हैं नज़र।

\*\*\*\*\*

राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली जाने वाली परीक्षा को ऑनलाइन मोड में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्णय परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए लिया गया है।

\*\*\*\*\*

केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने के समय अवधि में बढ़ोत्तरी की है।

\*\*\*\*\*

रांची नगर निगम ने शहर में बिना नक्शे और आदेश के चलाये जा रहे 36 रुफ टॉप रेस्टोरेंट का सर्वे का काम पूरा कर लिया है। निगम कोर्ट के अतिरिक्त प्रशासक संजय कुमार की बैंच ने सभी रेस्टोरेंट के मालिकों को सात जनवरी तक अपना पक्ष रखने का समय दिया है। संजय कुमार ने बताया कि कई रेस्टोरेंट मलिकों ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है।

\*\*\*\*\*

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक राज्य के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जतायी है। 28 दिसंबर को रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, लोहरदगा, गुमला, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा में हल्की बारिश हो सकती है जबकि 29 दिसंबर को कोल्हान, रांची, खूंटी, सिमडेगा और गुमला में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 30 दिसंबर को सुबह कोहरा और धुंध रहेगा। इसके बाद मौसम साफ हो जायेगा। मौसम वैज्ञानिक अभियंता ने बताया कि अगले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में कर्मी होने की संभावना नहीं है उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में कमी आयेगी।

\*\*\*\*\*

राजधानी रांची के खेलगांव में जनवरी में होने वाले 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेलों की मेजबानी की तैयारी अंतिम चरण में है। इसके आयोजन को लेकर राज्य शिक्षा परियोजना के निदेशक शशि रंजन ने बताया कि तीन जनवरी से खिलाड़ियों का आगमन होगा। निदेशक ने कहा कि खेल से जुड़े सभी पदाधिकारियों को आयोजन को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी तैयारी जल्द पूरी करने को कहा है।

\*\*\*\*\*